

भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2147
14 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए नियत

“फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों का विनिर्माण एवं आपूर्ति”

2147. श्री पी.वी. मिथुन रेड्डी:

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) फास्टर एडॉप्शन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम) स्कीम के चरण-1 और चरण-11 के परिणामस्वरूप निर्मित और आपूर्ति किए गए इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) का प्रकार/श्रेणी-वार ब्यौरा और संख्या कितनी है;
- (ख) फेम चरण-11 के तहत आंध्र प्रदेश राज्य के लिए और/या राज्य में कितने ईवी और स्ट्रॉंग हाइब्रिडों का निर्माण किया गया है;
- (ग) क्या सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के ईवी वाहनों की ब्रिकी और मांग के स्तर का आकलन किया है;
- (घ) यदि हां, तो, उक्त आकलन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और 2018-19 से लेकर अब तक फेम स्कीम के लाभार्थी के रूप में आंध्र प्रदेश की स्थिति क्या है; और
- (ङ) वर्ष 2018-19 से आंध्र प्रदेश में इस स्कीम के तहत आबंटित, जारी और उपयोग की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) : भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवी) के अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015 में भारत में (हाइब्रिड एवं) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम तैयार की थी। वर्तमान में, फेम इंडिया स्कीम के चरण-11 को कुल 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से 01 अप्रैल, 2019 से 5 वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

स्कीम के प्रथम चरण में, मांग प्रोत्साहन/सब्सिडी के माध्यम से लगभग 2.8 लाख हाइब्रिड वाहनों(एक्सईवी) के लिए सहायता प्रदान की गई। साथ ही, स्कीम के प्रथम चरण के तहत यथा संस्वीकृत 425 इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बसें देश के विभिन्न शहरों में तैनात की गई हैं।

15.02.2023 की स्थिति के अनुसार, फेम इंडिया स्कीम के चरण-11 के अंतर्गत मांग प्रोत्साहन के माध्यम से 8,82,967 इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सहायता प्रदान की गई है। साथ ही, भारी उद्योग मंत्रालय ने इस स्कीम के तहत 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इंटरसिटी और इंटरसिटी प्रचालन हेतु 65 शहरों/एसटीयू/सीटीयू/राज्य सरकार की इकाईयों के लिए 6315 ई-बसें संस्वीकृत की हैं।

(ख) : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिनांक 09.03.2023 की स्थिति के अनुसार आंध्रप्रदेश राज्य में कुल 51,604 इलेक्ट्रिक वाहन (ई-दुपहिया, ई-तिपहिया और ई-चौपहिया और उससे ऊपर के) पंजीकृत हैं।

(ग) और (घ) : जी नहीं। भारी उद्योग मंत्रालय ने फेम इंडिया स्कीम, चरण-11 के अंतर्गत इस संबंध में ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है। किंतु, फेम स्कीम के चरण-1 का मूल्यांकन एक स्वतंत्र परामर्शदाता द्वारा किया गया था। परामर्शदाता द्वारा प्रस्तुत निष्कर्ष रिपोर्ट के सत्यापन के मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

- (i) इस स्कीम से जागरूकता बढ़ी है जो अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
- (ii) ईंधन की बचत और कार्बन डाइऑक्साइड में कमी के मुख्य मानदंडों के समग्र परिणाम फेम के निर्धारित लक्ष्य से काफी कम हैं;
- (iii) उद्योग से जुड़ी कंपनियां क्षमता विकास को लेकर सावधानी बरत रही हैं। कंपनियों ने अपनी मुख्य क्षमताओं के आसपास प्रचालन को चुना है।
- (iv) पॉवर ट्रेन प्रौद्योगिकी (स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करने के लिए) के आधार पर सब्सिडी संरचना को पुनरीक्षित करने और प्रौद्योगिकियों में समरूपता स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, फेम इंडिया स्कीम, चरण-11 के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में पिछले कुछ वर्षों में काफी वृद्धि हुई है जो नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट है:

विवरण	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23 (15 फरवरी 2023 तक) (वाहनों की संख्या लाख में)
पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन	0.19	0.48	2.39	5.76

(च) : फेम इंडिया स्कीम, चरण-11 को कुल 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से 1 अप्रैल, 2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सहित अखिल भारतीय आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है।

15.02.2023 की स्थिति के अनुसार, फेम इंडिया स्कीम, चरण-11 के अंतर्गत मांग प्रोत्साहन के माध्यम से 8,82,967 इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सहायता प्रदान की गई है। साथ ही, भारी उद्योग मंत्रालय ने इस स्कीम के तहत 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इंद्रासिटी और इंटरसिटी प्रचालन के लिए 65 शहरों/एसटीयू/सीटीयू/राज्य सरकार की इकाइयों के लिए 6315 ई-बसें स्वीकृत की हैं।

मंत्रालय ने फेम इंडिया (भारत में हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण) स्कीम, चरण-11 के तहत 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 68 शहरों में 2877 चार्जिंग स्टेशनों को भी संस्वीकृति दी है।

फेम-इंडिया स्कीम, चरण-11 को कार्यान्वित करने के लिए बजट आवंटन और उपयोग का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	बजट आवंटन	28.02.2023 की स्थिति के अनुसार निधि का उपयोग
1	2019-2020	500.00 करोड़ रुपये	500.00 करोड़ रुपये
2	2020-2021	318.36 करोड़ रुपये	318.36 करोड़ रुपये
3	2021-2022	800.00 करोड़ रुपये	800.00 करोड़ रुपये
4	2022-2023	2903.08 करोड़ रुपये	1217.00 करोड़ रुपए (लगभग)